बड़े तालाब कैचमेंट में 7 निर्माण जमींदोज

एनजीटी के आदेश पर प्रशासन ने की कार्रवाई

16 मार्च 2022 के बाद के निर्माण हटाए जा रहे हैं

सिटी रिपोर्टर

भोपाल, 4 जुलाई. बड़े तालाब के फुल टैंक लेवल एफटीएल क्षेत्र से सटे तथा कैचमेंट एरिया में बने अवैध निर्माणों पर शनिवार को प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की.

इस दौरान कुल 7 निर्माणों को जमींदोज कर दिया गया.इन निर्माणों को हटाने के आदेश 21 अप्रैल को जारी किए गए थे, जिसके बाद 4 जुलाई को एसडीएम अर्चना रावत शर्मा के मार्गदर्शन में नगर निगम की बिल्डिंग परमिशन शाखा और अतिक्रमण शाखा ने पुलिस की मौजूदगी में यह कार्रवाई की.

कार्रवाई के दौरान सेवनिया गोंड में बनी पत्थरों की बाउंड्रीवॉल, गोरागांव में बने फार्म हाउस और मकान तथा बिशनखेड़ी क्षेत्र में कैचमेंट एरिया के भीतर बनी बाउंड्रीवॉल को तोड़ा गया. यह पहली बार है जब प्रशासन ने झुग्गियों, गुमटियों और टीनशेड के अलावा पक्के निर्माणों पर भी कार्रवाई की है. गोरागांव में निर्माणाधीन मैरिज गार्डन में बने भवन, टीनशेड और बाउंड्रीवॉल सहित सभी पक्के निर्माण भी हटाए गए. यह कार्रवाई नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एफटीएल के आदेश के तहत की जा रही है, जिसमें तालाब के कैचमेंट एरिया से 50 मीटर के दायरे में बने सभी पक्के निर्माणों को हटाने के निर्देश दिए गए हैं. मार्च से जिला प्रशासन द्वारा सर्वे कर अवैध निर्माणों की पहचान की गई थी, जिसके बाद चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई की जा रही है. याचिकाकर्ता राशिद नूर खान ने कहा कि इन निर्माणों से बारिश के दौरान तालाब तक जल प्रवाह प्रभावित होता है. कार्रवाई से भविष्य में अवैध निर्माणों पर रोक लगेगी और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा.

> प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि 16 मार्च 2022 के बाद बने सभी निर्माणों को प्राथमिकता से हटाया जा रहा है. एसडीएम अर्चना रावत शर्मा ने कहा कि एनजीटी के निर्देशों के अनुसार कार्रवाई लगातार जारी रहेगी.

आरोपियों की सूचना देने वाले को मिलेंगे 50 हजार

बुजुर्ग दंपति हत्याकांड : पुलिस कमिश्नर ने की घोषणा

नवभारत रिपोर्टर

भोपाल, 4 जुलाई. पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने बुजुर्ग दंपति हेमंत फिलेमोन और शकुंतला बारीक की हत्या की साजिश से जुड़ी पुख्ता सूचना देने वाले को 50 हजार रुपए का इनाम देने की शनिवार को घोषणा की है. ऐशबाग थाना इलाके में दंपति की हत्या के आरोपी पुलिस की पकड़ से अभी दूर हैं.

पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों की अगुवाई में आरोपियों की तलाश जारी है. आयुक्त ने पुलिस उपायुक्त क्राइम जोन 01 अखिल पटेल और 12 सदस्यीय विशेष जांच दल के साथ भौतिक और तकनीकी साक्ष्यों के विश्लेषण में तेजी लाने के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस की अब तक की जांच में जांचकर्ताओं ने दंपति के आवास से संवेदनशील कानूनी फाइलें बरामद कीं है. ये फाइलें मृतकों को चर्च की एक विवादित संपत्ति से जोड़ते हैं, जिस पर वर्तमान में धोखाधड़ी से भूमि बिक्री को लेकर अदालत में विवाद चल रहा है. इस पर साइबर क्राइम ब्रांच की जांच जारी है. नि:संतान दंपति को ये गोपनीय फाइलें कैसे मिलीं और क्या यह मुकदमा हत्या का मुख्य कारण था.

> जानकारी के मुताबिक बुजुर्ग दंपति हेमंत फिलेमोन और शकुंतला बारीक की हत्या के मामले में पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी है. हमलावर ने बुजुर्गों का मोबाइल भी मौके से गायब कर दिया था. पुलिस ने इससे पहले कजलीखेड़ा इलाके में उनके दो मोबाइल फोन एक व्यक्ति के पास से बरामद किए हैं. पुलिस ने जिस व्यक्ति से मोबाइल फोन बरामद किए. उसने यह फोन 300 रूपए देकर एक सफाईकर्मी से खरीदा था. सफाईकर्मी ने एक नाले की सफाई के दौरान मोबाइल मिलने की जानकारी पुलिस को दी गई. वारदात के करीब एक सप्ताह बाद भी आरोपी अभी भी पकड़े नहीं गए हैं.

सड़कों से आवारा पशुओं को हटाने की कार्रवाई तेज

भोपाल. नगर निगम द्वारा शहर की सड़कों, फुटपाथों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाले पशुओं को हटाने का अभियान लगातार जारी है. इसी क्रम में निगम के गौवर्धन परियोजना शाखा के अमले ने शनिवार को विभिन्न क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए कुल 34 पशुओं को पकड़कर कांजी हाउस भेजा, जबकि 5 बीमार एवं घायल पशुओं को आसरा पशु चिकित्सालय पहुंचाया गया. नगर निगम द्वारा हाका पार्टी की मदद से 15 पशुओं को सड़कों से हटाया गया तथा 20 पशुओं को जीवदया गौशाला भेजा गया.

फॉरेंसिक जांच से होगी आरोपियों की पहचान

आरजीपीवी में पेपर के बंडल चोरी का मामला

नवभारत रिपोर्टर

भोपाल, 4 जुलाई. राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में एग्जाम कंट्रोलर के कार्यालय से पेपर के बंडल चोरी के मामले में जांच शुरू कर दी गई है. विवि में बीटेक पेपर चोरी का मामला सामने आया है.

गांधीनगर थाना पुलिस ने इस पर फॉरेंसिक जांच शुरू की है. पुलिस को आरोपियों के फिंगर प्रिंट से लेकर अन्य साक्ष्य मिल सकते हैं. इसके आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंच सकती है. पुलिस मामले में आरजीपीवी के अधिकारियों को भी नोटिस जारी कर उनसे पूछताछ करेगी. 1 जुलाई की शाम कार्यालय में स्थित एग्जाम कंट्रोल का कमरा बंद होने के बाद कर्मचारी चले गए थे. दूसरे दिन सुबह जब एग्जाम कंट्रोल के गेट का कुंडी कर्मचारियों ने उखड़ी देखी. अंदर जाकर देखा तो पाया कि अलमारी में रखे में चौथे सेमेस्टर के पेपर बंडल गायब हैं. शिकायत मिलने पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. बताया जा रहा है कि कार्यालय में जहां पेपर चोरी हुए हैं, वहां पर सीसीटीवी कैमरे भी नहीं लगे हैं.

हॉस्टल पर बदमाशों ने किया पथराव

भोपाल. पिपलानी इलाके में संचालित एक हॉस्टल पर कुछ बदमाशों ने पथराव कर दिया. दहशत फैलाने वाले संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में लिया है. आरोपियों से मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है. जानकारी के मुताबिक पटेल नगर में शुक्रवार रात एक हॉस्टल पर पथराव किया गया. मामले की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची. घटना स्थल पर लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए पुलिस ने संदिग्धों को हिरासत में लिया है. हॉस्टल संचालक दुर्गेश तिवारी ने पथराव कराने की घटना को लेकर एक पुष्पराज यादव नाम के व्यक्ति पर आरोप लगाए हैं.

जेपी अस्पताल की दीवारों पर पान-गुटके के पीक

वार्ड के बाहर रखे डस्टबिन और दीवार लाल

सीढ़ियों पर सफाई न होने पर लगे निशान

वाटर कूलर के पास लगी गंदगी

नवभारत प्रतिनिधि

भोपाल, 4 जुलाई. जयप्रकाश जिला चिकित्सालय में सफाई कब की जाती है लोगों को पता भी नहीं चलता, जिसका प्रमाण अस्पताल परिसर में जगह- जगह पान, गुटके के पीक से चलता है. कुछ यही हाल इन दिनों महिला मेडिकल वार्ड के बाहर का है. जहां रखा डस्टबिन और दीवार लाल हो चुकी है. इतना ही नहीं परिसर में ऐसे

दीवारों के दागों की नहीं की जाती सफाई

और भी डस्टबिन और दीवारों पर लगे ये पान के पीक परिसर में सफाई की चरमराई व्यवस्था को बखूबी दिखाते नजर आते हैं. बता दें ये निशान एक दो दिन नहीं बल्कि कई दिनों से लगे हैं लेकिन इनकी सफाई नहीं की जा रही.

सफाई के नाम पर की जाती है खानापूर्ति

इस कारण यहां से जाने वाले मरीज भी मुंह दबाकर गुजरते हैं. वार्ड के मरीजों के अनुसार सफाई के नाम पर अधिकतर खानापूर्ति की जाती है. दीवार और डस्टबिन पर लगे दाग से तो की मतलब ही नहीं है. इस संबंध में सीएमएचओ से फोन के जरिये संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन बात नहीं हो सकी.

छात्रावास विद्यार्थियों ने सौंपा मांगों का ज्ञापन

भोपाल, 4 जुलाई . शासकीय डॉ. आंबेडकर अनुसूचित जाति छात्रावास, श्यामला हिल्स के विद्यार्थियों ने छात्रहित से जुड़ी विभिन्न मांगों को लेकर अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण विभाग के समक्ष रैली निकालकर ज्ञापन सौंपा.

इसके बाद विद्यार्थियों ने कमिश्नर कार्यालय तक पहुंचकर अपनी साथ ही विद्यार्थियों के प्रवेश पर सोमवार को कलेक्टर की अध्यक्षता में सहायक आयुक्त द्वारा रुल 2026 के प्रावधानों के तहत निर्णय लिया जाएगा.अधिकारियों ने यह भी बताया कि वर्तमान 40 सीटों के स्थान पर विद्यार्थियों के हित में 50 सीटों तक प्रवेश की अनुशंसा की गई है.

> प्रशासन ने सभी मांगों पर गंभीरता से विचार कर शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया है. विद्यार्थियों ने प्रशासन के आश्वासन का स्वागत करते हुए कहा कि यदि समयबद्ध समाधान नहीं होता है तो वे शांतिपूर्ण आंदोलन करने को बाध्य होंगे.

एमपी पुलिस ने अधिकारियों को दिया प्रशिक्षण

विशेष संवाददाता

भोपाल, 4 जून. मध्यप्रदेश पुलिस ने वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए दो दिवसीय प्रशिक्षण सेमीनार का सफलतापूर्वक समापन किया.

भोपाल स्थित मध्यप्रदेश पुलिस अकादमी में आयोजित इस सेमीनार में प्रदेशभर से उप पुलिस अधीक्षक एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों ने भाग लिया. समापन सत्र को संबोधित करते हुए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सोलोमन यश कुमार मिंज ने कहा कि वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही किसी भी शासकीय संस्था की कार्यकुशलता की आधारशिला हैं. उन्होंने अधिकारियों से प्रशिक्षण के दौरान अर्जित ज्ञान का उपयोग अपने-अपने कार्यक्षेत्र में करते हुए वित्तीय प्रक्रियाओं को अधिक नियमसम्मत, पारदर्शी और प्रभावी बनाने का आह्वान किया. सेमीनार के उद्घाटन सत्र में पुलिस मुख्यालय के उप पुलिस महानिरीक्षक अवधेश गोस्वामी ने अधिकारियों को बदलते वित्तीय नियमों की अद्यतन जानकारी रखने तथा वित्तीय दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करने की आवश्यकता पर बल दिया. दो दिवसीय प्रशिक्षण के दौरान पुलिस मुख्यालय, वित्त विभाग तथा कोष एवं लेखा निदेशालय के विशेषज्ञों ने खरीद नियमों, आईएफएमआईएस पेंशन नियम, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, बजट प्रबंधन, कल्याणकारी योजनाओं, अवकाश नियम, जीपीएफ प्रक्रियाओं, टीए/ डीए दावों तथा वित्तीय शक्तियों से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तृत जानकारी देकर अधिकारियों की वित्तीय प्रबंधन क्षमता को सुदृढ़ किया.

साइबर अपराध के खिलाफ मैराथन दौड़

विशेष संवाददाता

भोपाल, 4 जुलाई . मध्यप्रदेश पुलिस के प्रदेशव्यापी सेफ क्लिक 2.0 साइबर जागरूकता अभियान के तहत शनिवार को शासकीय रेल पुलिस (जीआरपी) भोपाल ने पांच किलोमीटर की साइबर जागरूकता मैराथन का आयोजन किया.

मैराथन का उद्देश्य बढ़ते साइबर अपराधों के प्रति आमजन को जागरूक करने के साथ-साथ पुलिस बल में शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देना रहा. मैराथन को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (रेल) राजाबाबू सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस अवसर पर पुलिस उपमहानिरीक्षक (रेल) पंकज श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक (रेल), भोपाल अंकित जायसवाल सहित लगभग 150 रेल पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे. मैराथन के दौरान प्रतिभागियों ने ऑनलाइन ठगी, फिशिंग, फर्जी कॉल, ओटीपी धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट और नकली निवेश योजनाओं जैसे साइबर अपराधों से बचाव का संदेश दिया. लोगों से संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करने, बैंकिंग संबंधी गोपनीय जानकारी और पासवर्ड साझा न करने तथा साइबर ठगी होने पर तुरंत राष्ट्रीय हेल्पलाइन 1930 या राष्ट्रीय साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने की अपील की गई.

हरियाली को बढ़ावा देने का दिया संदेश

भोपाल. पर्यावरण संरक्षण और हरियाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पौधारोपण का शनिवार को आयोजन किया गया. मुख्य अतिथि के रूप में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक रेल भोपाल राजाबाबू सिंह, उप पुलिस महानिरीक्षक रेल पंकज श्रीवास्तव एवं पुलिस अधीक्षक रेलवे भोपाल अंकित जायसवाल उपस्थित रहे. राजाबाबू सिंह ने पहला पौधा लगाया. उन्होंने कहा कि हमें न सिर्फ पौधे लगाने हैं, बल्कि उनके बड़े होने तक उनकी देखभाल का संकल्प भी लेना होगा.

कोलार के दो कुख्यात बदमाश जिलाबदर

भोपाल. पुलिस आयुक्त ने कोलार थाना पुलिस के प्रतिवेदन पर कार्रवाई करते हुए क्षेत्र के दो कुख्यात बदमाशों को एक वर्ष के लिए जिलाबदर कर दिया है. आरोपी जीतू यादव को भोपाल सहित आसपास के जिलों की सीमा में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाया गया है. आरोपी रोहित ओसवाल को भी 1 वर्ष के लिए जिलाबदर किया गया है. पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से यह कार्रवाई की गई है.

युवक की पिटाई कर आरोपी ले गए कार

भोपाल. कोहेफिजा थाना इलाके में एक युवक की पिटाई करते हुए उसकी 9 लाख रुपए की कीमत की कार लूट का मामला सामने आया है. पंचवटी कॉलोनी एयरपोर्ट निवासी 27 वर्षीय सौरभ सितलानी ने शिकायत दर्ज कराई है. वह शुक्रवार को अपने दोस्तों के साथ देर रात खाना खाने के लिए एक ढाबे पर गये थे. लौटते समय दोस्त बाबर को साथी आदित्य शर्मा को फोन आया. आदित्य ने सभी को मनुवाभान टेकरी के गेट पर मिलने बुलाया और सभी कार से वहां पहुंचे. इस दौरान आदित्य ने सौरभ से रुपए की मांग की. रुपए नहीं देने पर सभी ने मिलकर सौरभ के साथ मारपीट की और उसकी कार लेकर चले गए.

अपहरण करने वाला गिरफ्तार आरोपी पर दर्ज हैं कई मामले

नवभारत रिपोर्टर

भोपाल, 4 जुलाई. अशोका गार्डन इलाके में नौ साल की बच्ची के अपहरण के प्रयास के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपी आदतन यौन अपराधी है. इससे पूर्व भी उस पर महिलाओं और नाबालिग लड़कियों के अपहरण और यौन उत्पीड़न के पुराने केस दर्ज हैं. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है.

जानकारी के मुताबिक आरोपी की पहचान मून बहादुर नाम के व्यक्ति के रूप में की गई है. आरोपी मूलत: नेपाल का रहने वाला है और रसोइया का काम करता है. उसके खिलाफ ऐशबाग और जहांगीराबाद पुलिस स्टेशनों में नाबालिगों के साथ बलात्कार के दो मामले और युवतियों के अपहरण के दो मामले दर्ज हैं. बीते मंगलवार को मून बहादुर ने बच्ची को उसके पिता का दोस्त बताकर अपहरण किया था. बच्ची उस दौरान मंदिर से पूजा करके अकेले ही अपने घर की तरफ जा रही थी. आरोपी अपनी बाइक पर बैठाकर बच्ची को लेकर कई इलाकों में घूमा. बच्ची के लगातार रोने पर वह उसे अरेरा हिल्स इलाके में छोड़कर फरार हो गया. राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और बच्ची को उसके परिजनों से मिलाया.

समस्या | 6 महीने से नहीं मिला वेतन, आर्थिक संकट से जूझ रहे परिवार

वेतन के लिए तरस रहे आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मी

- कर्मचारी संघ कर चुका है धरना-प्रदर्शन
- डेटा पोर्टल पर नहीं किया अपलोड

नवभारत प्रतिनिधि

भोपाल, 4 जुलाई. प्रदेशभर के शासकीय अस्पतालों में सेवाएं दे रहे आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी पिछले 5 से 6 महीनों से वेतन न मिलने के कारण गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं.

बता दें निजी आउटसोर्स एजेंसियों के संचालकों और विभागीय अधिकारियों की मनमानी को लेकर मप्र संविदा आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी संघ लंबे समय से राजधानी में बड़े धरना-प्रदर्शन और आंदोलनों के माध्यम से सरकार तक अपनी आवाज पहुंचा रहा है, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है. वित्त विभाग ने 28 मार्च को एक आदेश जारी किया था.इसके तहत विभिन्न निजी और शासकीय एजेंसियों के नियोजन, अनुबंध प्रबंधन और प्रशासनिक नियंत्रण के लिए रिसोर्स आउटसोर्सिंग एजेंसी मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल का उपयोग अनिवार्य किया गया था.आदेश के मुताबिक 1 अप्रैल से 30 जून तक सभी आउटसोर्स कर्मचारियों की जानकारी इस पोर्टल पर अपलोड की जानी थी.लेकिन अब तक यह जानकारी अपलोड नहीं की गई है. जिसको लेकर संगठन का कहना है कि वर्तमान में निजी आउटसोर्स एजेंसियों को 10 प्रतिशत सर्विस चार्ज मिलता है, जबकि रोम्स पोर्टल पूरी तरह लागू होने के बाद यह सर्विस चार्ज घटकर महज 1 प्रतिशत रह जाएगा. इसके अलावा पोर्टल के माध्यम से निर्धारित समय पर पूरा वेतन भुगतान करना अनिवार्य हो जाएगा. इसी मुनाफे को बचाने के लिए निजी कंपनियों के संचालकों के रसूख और विभागीय अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण डेटा पोर्टल पर अपलोड ही नहीं किया गया.

> **सरकार के आदेश बेअसर**
>
> हैरानी की बात यह है कि सरकार ने जिस व्यवस्था को आउटसोर्स कर्मचारियों के शोषण पर रोक लगाने के लिए तैयार किया था. वह अपने ही उस आदेश का पालन करवाने में नाकाम साबित हो रही है .अब इस गंभीर समस्या का स्थायी समाधान निकालने के लिए अब यह मांग जोर पकड़ रही है कि सरकार इस शोषणकारी आउटसोर्स प्रथा को पूरी तरह बंद करे. साथ ही कर्मचारियों के भविष्य को देखते हुए उन्हें स्थायी कर्मी का दर्जा दिया जाए, ताकि उन्हें हर महीने समय पर वेतन मिल सके.

अतिथि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू

90 प्रतिशत से अधिक ई- अटेंडेंस वाले ही कर सकेंगे आवेदन

नवभारत प्रतिनिधि

भोपाल, 4 जुलाई. लोक शिक्षण संचालनालय ने सत्र 2026-27 के लिए खाली पड़े पदों पर अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में दिशा निर्देश और समय सारणी जारी कर दी है.

विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार इस बार पूरी भर्ती प्रक्रिया को ऑनलाइन और बेहद पारदर्शी बनाया गया है. साथ ही इसमें ऑफलाइन आमंत्रण पर पूरी तरह रोक लगाई गई है. वहीं इस बार स्कूलों में खाली पदों की सही जानकारी जुटाने के लिए विभाग ने शाला प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि वे केवल वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही पोर्टल पर खाली पदों की दर्ज करें. जानबूझकर या बिना जरूरत के पद दिखाने पर कार्रवाई हो सकती है. पहले चरण के तहत लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म रिक्तियों के अपडेट और जीएफएमएस पोर्टल पर प्रदर्शन का काम 1 जुलाई से शुरू हो चुका है, जो 6 जुलाई तक चलेगा. इसके बाद अलग-अलग चरणों में मेरिट और स्कोर कार्ड के आधार पर शाला विकल्प चयन और आवंटन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. इस बार के नियमों में सबसे बड़ा बदलाव री जॉइनिंग को लेकर किया गया है.

> पिछले सत्र में काम कर चुके जिन आवेदकों की ई अटेंडेंस नब्बे प्रतिशत या उससे अधिक रही है, केवल वही इस सत्र में री जॉइनिंग के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे. विभाग ने साफ कर दिया है कि जो अतिथि शिक्षक निर्धारित समय सीमा में एप के माध्यम से अपनी डिजिटल हाजिरी दर्ज नहीं करेंगे, उस दिन का उनका मानदेय जनरेट नहीं किया जाएगा. इसके अलावा यदि कोई अतिथि शिक्षक ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं करता है तो उसे मानदेय की पात्रता ही नहीं होगी.